

हिन्दी प्रादेशिक समाचार
आकाशवाणी चंडीगढ़
(तिथि 12 अगस्त 2025, समय 1305 (05 मिनट))

आधार चेहरा प्रमाणीकरण प्रणाली ने इस वर्ष 10 अगस्त तक दो अरब लेनदेन का आंकड़ा पार कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केवल छह महीनों में लेनदेन की संख्या एक अरब से दोगुनी हो गई है। इस प्रणाली से बिना किसी दस्तावेज़ या शारीरिक संपर्क के, केवल चेहरे का उपयोग करके पहचान सत्यापित की जाती है। सुरक्षित और तेज़ प्रणाली उपयोग कभी भी, कहीं भी किया जा सकता है। आधार चेहरा प्रमाणीकरण के उप महानिदेशक मनीष भारद्वाज ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि प्राधिकरण ने कम समय में यह आंकड़ा दो सौ करोड़ के पार कर लिया है।

फेस ऑथेंटिकेशन या चेहरा प्रमाणीकरण आधार की तेजी से उभरती हुई प्रणालिका है जिसमें मोबाइल के जरिए आधार सत्यापन चंद्र सेकंड में किया जा सकता है। इस प्रणालिका के माध्यम से अब तक दो सौ करोड़ ट्रांज़ैक्शंस हो चुके हैं और इस प्रणालिका का उपयोग भारत सरकार के अनेक योजनाओं में बेनिफिशियरी के सत्यापन के लिए किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत आज पलवल जिला प्रशासन द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम से विशाल तिरंगा साइकिल यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर जिला उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ, पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला एवं भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन बैसला सहित जिला प्रशासन के अधिकारी शामिल हुए। डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा भव्य तिरंगा साइकिल यात्रा निकाली गई। जिसमें चार से पांच हजार लोगों ने भाग लिया। तिरंगा यात्रा में जिला प्रशासन के साथ साथ आमजन की भागीदारी भी रही।

उपायुक्त ने कहा कि इस दौरान युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया गया। उन्होंने बताया कि यह तिरंगा यात्रा नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम से शुरू होकर सोहना शहर चौक, पुराना सोहना रोड, सेक्टर दो सोहना मोड़, अलावलपुर चौक, रसूलपुर चौक, रसूलपुर बर्फखाना से श्रद्धानंद पार्क, आगरा चौक होते हुए वापस नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आकर समाप्त हुई। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन बैसला ने लोगों से हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया।

हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने कल विधान भवन में शोध केंद्र और पुस्तकालय के नवीनीकरण का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस विधान सभा शोध केंद्र में विधायकों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए अध्ययन एवं शोध का अनुकूल वातावरण और संसाधन उपलब्ध होंगे। केंद्र में उच्चस्तरीय संदर्भ सामग्री, डिजिटल डेटाबेस और संसदीय व विधायी दस्तावेजों का सुव्यवस्थित संकलन उपलब्ध कराया जाएगा।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में कल राज्य के विभिन्न विभागों से जुड़ी लगभग 1763 करोड़ रुपये से ज्यादा की विभिन्न वस्तुओं के खरीद प्रस्तावों एवं रेट कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकृति प्रदान की गई। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से बातचीत के बाद दरें तय करके लगभग 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की बचत की गई है। मुख्यमंत्री ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए और तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता जनता को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना है। हरियाणा सरकार वित्तीय संसाधनों के बेहतर उपयोग और पारदर्शी खरीद प्रणाली के माध्यम से विकास कार्यों को समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में कानून एवं व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत से 29 नई 52 सीटर बसें और 6 मिनी बसों की खरीद को भी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा, विद्युत आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा लगभग 234 करोड़ 19 लाख रुपये की लागत से एलटी एक्स एल पी ई आर्मर्ड केबल, विभिन्न पोल तथा 20 किलो वाट एमपीयर के ट्रांसफार्मर की खरीद को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विद्युत केबल की गुणवत्ता की जांच मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में कराई जाए और यदि कोई नमूना गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरता, तो संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्युत उपकरणों और सामग्रियों की खरीद में सुरक्षा मानकों के दृष्टिगत किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए, ताकि सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित हो सके। बैठक में शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी पैप उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अलावा, बैठक में डिजिटल सेवाओं के विस्तार और ई-गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए उपकरणों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। इसके लिए लगभग 3 करोड़ 20 लाख रुपये से ज्यादा की लागत से क्लाउड सर्वर और स्टोरेज क्षमता सेवाओं को मजबूत करने की हिदायत की गई। इससे राज्य में सरकारी सेवाओं के वितरण में पारदर्शिता, गति और कुशलता को और बढ़ावा मिलेगा।
